

APJ

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 33/2022

1. इन्द्राज सिंह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राम सिंह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. राजेश पुत्र दयानन्द, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. महावीर पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

--- अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुमार पुत्र पूर्ण, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. विजय सिंह पुत्र पूर्ण, जाति जाट, निवासी मीलो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

--- रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ विनियम आदेश दिनांक 18.10.2010 कार्यालय तहसीलदार झुंझुनूं बाबत खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास ।

उपस्थित

1. श्री रवि कुमार, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट्स सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोंडेन्ट सं0 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 18.10.2010 बाबत खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। निवेदन है कि जमीन खसरा नं0 963 व 984 वाके ग्राम उदावास पटवार हल्का कुलोद कलां तहत तहसील झुंझुनूं में स्थित है। अदालत मातहत ने बिना किसी सक्षम आदेश के आलौच्य विनियम आदेश दिनांक 18.10.2010 पारित किया है जिसके विरुद्ध मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि जमीन खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर के वर्तमान खसरा नं0 1183/963 रकबा 0.2684 हैक्टर खसरा नं0 1184/963 रकबा 0.0056 हैक्टर, खसरा नं0 1182/963 रकबा 0.0200 हैक्टर व खसरा नं0 984 रकबा 1.33 हैक्टर के वर्तमान खसरा नं0 984 रकबा 1.10 हैक्टर व खसरा नं0 1082/984 रकबा 0.23 हैक्टर पडे जो राजस्व ग्राम उदावास तहसील व जिला झुंझुनूं में स्थित है। अपीलान्ट्स के हिस्से में जमीन खसरा नं0 672, 762 व 963 कुल किता 3 कुल रकबा 4. हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके अपीलान्ट्स काबिज काश्तकार रहे है तथा वर्तमान समय में खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर काश्तकार अपीलान्ट्स थे एवं जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में भूमि खसरा नं0 963 रकबा 0.30 हैक्टर के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स थे एवं जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट्स दर्ज


जिला कलक्टर झुंझुनूं

AM

रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है लेकिन रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर दिनांक 18.10.2010 को एक विनियम आदेश के आधार पर खसरा नं० 963 की भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में 0.30 हैक्टर दर्ज करवा ली तथा अपीलान्ट्स के नाम अपने खसरा नं० 984 में से केवल 0.23 हैक्टर भूमि ही दर्ज करवाई। कानूनन विनियम आदेश में दोनों पक्षकारों की सहमति से बराबर बराबर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये। इस प्रकार उपरोक्त विनियम आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है एवं निरस्त होने योग्य है। किसी भी भूमि का विनियम जब किया जाता है तो विनियम की जाने वाली भूमि का रकबा समान होना चाहिए। उपरोक्त विनियम आदेश के बाद एक दावा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2015 को पेश किया जो मुकदमा उनवानी रामकुमार बनाम विजयसिंह वगैरह मु० नं० 218/2015 को दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कुलोद कलां में निर्णित करते हुये निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री में भूमि खसरा नं० 963 को भी शामिल किया जाकर विभाजन कर दिया जो निर्णय व डिक्री अपीलान्ट्स के हक हकूकों के विपरित होने से अपीलान्ट्स प्रभावित है। चूंकि रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया उसमें तथ्यों को छिपाते हुये दावा पेश किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 एवं 2062 से 2065 की जमाबन्दी में भूमि खसरा नं० 963 विभाजन के पश्चात् खसरा नं० 963 के बट्टा नम्बर 1183/963, 1184/963 व 1182/963 कायम हुये। रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी रामकुमार बनाम विजय सिंह वगैरह मु० नं० 218/2015 को अदालत हाजा को मुगालते में रखकर अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने पक्षकारों का कुसंयोजन कर निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने अपीलान्ट्स को उनके हक हकूकों से वंचित करते हुये दावा डिक्री करवाकर भूमि खसरा नं० 963 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि को अपने नाम निर्णय व डिक्री के आधार पर दर्ज करवा लिया। भूमि खसरा नं० 963 पर अपीलान्ट्स मौके पर काबिज काश्त है। दिनांक 10.05.2022 को रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने भूमि खसरा नं० 963 जिसके बट्टा नं० 1183/963, 1184/963 व 1182/963 पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा उक्त भूमि पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कर तारबन्दी करना चाह रहे थे तथा कहा कि अब उपरोक्त जमीन काफी कीमती है हम तुम्हे इस जमीन से बेदखल करके ही दम लेंगे। इस कारण अपीलान्ट्स को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पारित आलौच्य विनियम आदेश दिनांकित 18.10.2010 को निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तथा कथन किया कि अपील मेमो ही उसकी बहस मानी जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पारित आलौच्य विनियम आदेश दिनांकित 18.10.2010 को निरस्त किया जावे।

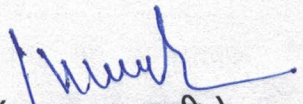
वकील रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विनियम सहमति से हुआ है। अपीलान्ट की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने बार-बार विवादित भूमि पर ऋण लिया है अतः यह कहना गलत है कि प्रकरण अपीलान्ट की जानकारी में नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट सं० 1 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विनियम सहमति से हुआ है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू ने विनियम आदेश दिनांक 18.10.2010 बाद जांच विधिवत् रूप से पारित किया है। अपीलान्ट की यह अपील अन्दर मियाद नहीं है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।


विनियम अपीलान्ट्स के समक्ष

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विनियम सहमति से हुआ है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश के 12 साल बाद पेश की है एवं अपीलान्ट ने बार-बार विवादित भूमि पर ऋण लिया है। अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि प्रकरण अपीलान्ट की जानकारी में नहीं था। अदालत मातहत पारित विनियम आदेश दिनांक 18.10.2010 आपसी सहमति से पारित किया गया है। आपसी सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट की यह अपील उचित नहीं मानी जा सकती है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन व चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फंसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुझुनूं
झुझुनूं